केंद्रीय कर आयुक्त (अपील)



O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), CENTRAL TAX,

वस्तु एवं सेवा कर भवन् GST Building ,7th Floor,, Near Polytechnic, Ambavadi, Ahmedabad-380015



सातवीं मंजिल,पोलिटेकनिकके पास, आम्बायाडी, अहमदाबाद-380015

: 079-26305065

टेलेफैक्स : 079 - 26305136

क फाइल संख्या :File No :**V2(SAS)13&14/AHD-III/2017-18** / **१**० 📆

Passed by Shri Uma Shanker Commissioner (Appeals)Ahmedabad

ग अपर आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद-॥ आयुक्तालय द्वारा जारी मूल आदेश : GNR-STX-DEM-DC-13/2017 दिनाँक : 08.03.2017 से सृजित

Arising out of Order-in-Original: **GNR-STX-DEM-DC-13/2017**, Date: **08.03.2017** Issued by: Assistant Commissioner, Service Tax, Div:Gandhinagar, Ahmedabad-III.

ध अपीलकर्ता एवं प्रतिवादी का नाम एवं पता

Name & Address of the Appellant & Respondent

M/s. Mahavir Enterprises

कोई व्यक्ति इस अपील आदेश से असंतोष अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथास्थिति नीचे बताए गए सक्षम अधिकारी को अपील या पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

Any person aggrieved by this Order-In-Appeal may file an appeal or revision application, as the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way:

भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन ः Revision application to Government of India :

- (1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा अंतर्गत नीचे बताए गए मामलों के बारे में पूर्वोक्त धारा को उप—धारा के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अवर सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली : 110001 को की जानी चाहिए।
- (i) A revision application lies to the Under Secretary, to the Govt. of India, Revision Application Unit Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi 110 001 under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid:
- (ii) यदि माल की हानि के मामले में जब ऐसी हानि कारखाने से किसी भण्डागार या अन्य कारखाने में या किसी भण्डागार से दूसरे भण्डागार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भण्डागार या भण्डार में चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भण्डागार में हो माल की प्रकिया के दौरान हुई हो।
- (ii) In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse.
- (ख) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयोग शुल्क कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क के रिबेट के मामलें में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित है।
- (b) In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.

- (ग) यदि शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया माल हो।
- (C) In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.
- ध अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो डयूटी केंडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में वित्त अधिनियम (न.2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हो।
- (d) Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act. 1998.
- (1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपन्न संख्या इए–8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनाँक से तीन मास के भीतर मूल–आदेश एवं अपील आदेश की दो—दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके साथ खाता इ. का मुख्यशीर्ष के अंतर्गत धारा 35–इ में निर्धारित फी के भुगतान के सबूत के साथ टीआर–6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(2) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रूपये या उससे कम हो तो रूपये 200/- फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्न रकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/- की फीस भुगतान की जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपीलः--Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35— णबी / 35—इ के अंतर्गत:—

Under Section 35B/ 35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-

उक्तलिखित परिच्छेद 2 (1) क में बताए अनुसार के अलावा की अपील, अपीलों के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में ओ—20, न्यू मैन्टल हास्पिटल कम्पाउण्ड, मेघाणी नगर, अहमदाबाद—380016.

To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at O-20, New Metal Hospital Compound, Meghani Nagar, Ahmedabad : 380 016. in case of appeals other than as mentioned in para-2(i) (a) above.

(2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 की धारा 6 के अंतर्गत प्रपन्न इ.ए—3 में निर्धारित किए अनुसार अपीलीय न्यायाधिकरणें की गई अपील के विरुद्ध अपील किए गए आदेश की चार प्रतियाँ सिहत जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या उससे कम है वहां रूपए 1000 /— फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या 50 लाख तक हो तो रूपए 5000 /— फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 50 लाख या उससे ज्यादा है वहां रूपए 10000 /— फीस भेजनी होगी। की फीस सहायक रिजस्टार के नाम से रेखाकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में संबंध की जाये। यह ड्राफ्ट उस स्थान के किसी नामित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की शाखा का हो

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise(Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of Rs.1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/- where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registar of a branch of any

nominate public sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated

(3) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल ओदश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होते हुए भी कि लिखा पढी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner not withstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.

(4) न्यायालय शुल्क अधिनियम 1970 यथा संशोधित की अनुसूचि—1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूल आदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रति पर रू.6.50 पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall beer a court fee stamp of Rs.6.50 paisa as prescribed under scheduled-litem of the court fee Act, 1975 as amended.

(5) इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में निहित है।

Attention in invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

(6) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सीस्तेत) के प्रति अपीलों के मामलों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, १९४४ की धारा ३५फ के अंतर्गत वितीय(संख्या-२) अधिनियम २०१४(२०१४ की संख्या २५) दिनाक: ०६.०८.२०१४ जो की वितीय अधिनियम, १९९४ की धारा ८३ के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, द्वारा निश्चित की गई पूर्व-राशि जमा करना अनिवार्य है, बशर्त कि इस धारा के अंतर्गत जमा की जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रूपए से अधिक न हो

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत " माँग किए गए शुल्क " में निम्न शामिल है

- . (i) धारा ११ डी के अंतर्गत निर्धारित रकम
- (ii) सेनवैट जमा की ली गई गलत राशि
- (iii) सेनवैट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम

→ आगे बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वितीय (सं. 2) अधिनियम, 2014 के आरम्भ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्ज़ी एवं अपील को लागू नहीं होगे।

For an appeal to be filed before the CESTAT, it is mandatory to pre-deposit an amount specified under the Finance (No. 2) Act, 2014 (No. 25 of 2014) dated 06.08.2014, under section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under section 83 of the Finance Act, 1994 provided the amount of pre-deposit payable would be subject to ceiling of Rs. Ten Crores,

Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules

→Provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

(6)(i) इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो माँग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती हैं।

(6)(i) In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute."

ORDER-IN-APPEAL

M/s. Shree Mahavir Enterprise, 19, Silver Park, Palace Road, Mahavirnagar, Himmatnagar, Sabarkantha (hereinafter referred to as 'appellants') have filed the present appeals against Order-in-Original number GNR-STX-DEM-DC-13/2017 dated 08.03.2017 (hereinafter referred to as 'impugned order') passed by the then Assistant Commissioner, Service Tax, Gandhinagar Division, Ahmedabad-III (hereinafter referred to as 'adjudicating authority').

- The facts of the case, in brief, are that the appellants are engaged in providing the service of 'Manpower Recruitment & Supply Agency' and are holding Service Tax Registration number AJKPM5149BSD002 from 08.05.2015 for the taxable services 'Manpower Recruitment & Supply Agency' and 'Business Support Service'. On the basis of inquiry, it was noticed that the appellants supplies unskilled labourer/ worker to M/s. Sabarkantha District Co-op Milk producers Union Ltd. (hereinafter referred to as 'M/s. Sabar Dairy'). During the course of further inquiry, it was noticed that the appellants had started providing services to M/s. Sabar Dairy from the year 2011-12 and had crossed the threshold limit of ₹10 lakhs in the year 2011-12 itself. However, it was verified that they failed to pay Service Tax on the income received in exchange of the services provided. Thus, after providing the threshold benefit of ₹10 lakhs to the appellants, their total Service Tax liability was calculated to be ₹38,52,501/- for the periods from 2011-12 to 2014-15. Accordingly, a show cause notice dated 20.09.2016, was issued to the appellants which was adjudicated by the adjudicating authority vide the impugned order. The adjudicating authority, vide the impugned order, confirmed Service Tax of ₹38,52,501/- (₹13,39,253/- for the period April 2011 to March 2013 + ₹25,13,248/- for the period April 2013 to March 2015) under Section 73 of the Finance Act, 1994. He also ordered for the recovery of interest under Section 75 of the Finance Act, 1994 and imposed penalty of ₹10,000/- each under Sections 77(1)(a) and 77(2) of the Finance Act, 1994 and ordered to recover late fee specified under Rule 7C of Service Tax Rule, 1994 for the above mentioned periods. He also imposed penalty of ₹6,69,627/- and ₹12,56,624/- respectively for the above mentioned periods under Section 78 of the Finance Act, 1994.
 - 3. Being aggrieved with the impugned order, the appellants filed the present appeal. The appellants stated that they deny all allegations imposed vide the impugned order. The appellants further argued that they were engaged in the execution of specific works like 'shreekhand' and 'lassi' at the plant of M/s. Sabar Dairy and same were covered under "Negative List" of services.

They further stated that the show cause notice has invoked extended period of limitation alleging that the appellants have suppressed the information from the department. But there is no suppression or willful wrong statement on the part of the appellants. They have further urged that penalties under Section 77(1)(a), 77(2) and 78 of the Finance Act, 1994 cannot be imposed in the present case.

- 4. Personal hearing in the case was granted on 16.11.2017 wherein Shri Ajit P Sandesara, Chartered Accountant, on behalf of the appellants appeared before me and reiterated the contents of appeal memorandum. He sought 2 days time to submit the copy of contract.
- 5. I have carefully gone through the facts of the case on records, grounds of the Appeal Memorandum, the Written Submission filed by the appellant and oral submission made at the time of personal hearing. To begin with, I find that there has been a delay occurred in filing the appeal by the appellants. The impugned order was issued on 08.03.2017 and the appellants have claimed, in Form ST-4, to have received the same on 14.03.2017. However, they have not submitted any documentary evidence in support of their claim. Mere verbal assertion has no legal base under the eyes of law. In view of the above, I find that the claim is delayed by 8 days and the appellants have not pleaded for condonation of delay. On this ground itself, I reject the appeal filed by the appellants. However, as per the principle of natural justice, I would like to discuss the case on merit.
- Now, I take the contention of the appellants pertaining to whether the 6. appellant was actually engaged in the service of manpower supply or carrying job work. In this regard I agree with the adjudicating authority that the appellant was involved in a contractual work with M/s. Sabar Dairy. The appellant's contention that they were having a relation under principal to principal basis with M/s. Sabar Dairy is not supported by any documentary evidence. Simply stating that they were not a labour supplier but doing specific work at site does not suffice the purpose of the appellants and it seems to be a mere afterthought on their part. The various conditions, mentioned in the contract, are very clear to emphasize the fact they are liable for payment of Service Tax. From condition number 4 to 21, it is very clear that all the liabilities regarding salary, bonus, uniform etc. were to be borne by the appellants (being the labour contractor). In condition number 47, M/s. Sabar Dairy directs the appellants to collect Service Tax from the former and pay the same. The appellants were bound by the contract to produce the challans as proof of payment. This is enough to conclude that the appellants were liable to pay Service Tax which they failed to do. In this regard, I proclaim that the adjudicating authority has rightly confirmed the demand of Service Tax amounting to ₹38,52,501/-.
- 7. Further, regarding his argument that no suppression can be invoked, I



would like to quote the judgement of Hon'ble CESTAT, Mumbai in the case of M/s. Daichi Karkaria Ltd. vs. CCE, Pune-I where the Hon'ble CESTAT, Mumbai proclaimed that;

"....if some information is available in various reports and returns which are to be formulated in compliance to other statutes, it does not lead to a conclusion that the utilization of credit for the activity of renting is known to the Department. The Department is not supposed to know each and every declaration made outside the Central Excise and Service Tax law. Even if the Financial Report is available to the audit, the same is meaningless in the sense that it does not indicate that input Service Tax credit utilized to pay the tax liability on such renting of property. The appellant's argument on limitation is rejected."

- 8. In view of the above, I uphold the levy of Service Tax as confirmed by the adjudicating authority vide the impugned order. Regarding the interest under Section 75 of the Finance Act, 1994, I uphold the same as the appellants have failed to pay up the Service Tax and is rightly invoked under the impugned order. Regarding imposition of penalty under various Sections of the Finance Act, 1994 and Service Tax Rules, 1994, I uphold the same.
- **9**. Accordingly, as per the above discussion, I do not find any reason to interfere in the impugned order and reject the appeal filed by the appellants.
- 10. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपीलों का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।
- 10. The appeals filed by the appellant stand disposed off in above terms.

(उमा शंकर)

आयुक्त (अपील्स - II)

CENTRAL EXCISE, AHMEDABAD.

ATTESTED

SUPERINTENDENT (APPEAL-II), CENTRAL EXCISE, AHMEDABAD.

BY R.P.A.D.

To,

M/s. Shree Mahavir Enterprise,

19, Silver Park, Palace Road,

Mahavirnagar, Himmatnagar,

Dst: Sabarkantha

Copy To:-

- 1) The Chief Commissioner, Central Tax, Ahmedabad.
- 2) The Commissioner, Central Tax, Gandhinagar.
- 3) The Dy./Asst. Commissioner, Central Tax, Himmatnagar Division, Gandhinagar Commissionerate.
- A) The Asst. Commissioner (System), Central Tax Hq., Gandhinagar.
- 5) Guard File.
- 6) P. A. File.

